



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 श्रावण 1937 (श10)
(सं० पटना 935) पटना, मंगलवार, 18 अगस्त 2015

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

4 अगस्त 2015

सं० वि०सं०वि०-15/2015- 2893/वि०सं०—“बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार विधेयक, 2015”, जो बिहार विधान-सभा में दिनांक 04 अगस्त, 2015 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार-विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
हरeram मुखिया,
प्रभारी सचिव ।

fcgkj ykd f'kdj r fuokj.k vf/kdjk fo/k d] 2015

[वि०संवि०-11/2015]

राज्य की जनता को नियत समय-सीमा के भीतर लोक शिकायत निवारण का अधिकार तथा उनसे सशक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो, :-

1- l f'kdj r fuokj.k vf/kdjk & (1) यह अधिनियम बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा राजपत्र में नियत करे।

2- ifjHkk a & इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

- (क) "परिवाद" से, अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा राज्य में चलाई जा रही किसी योजना, कार्यक्रम या सेवा के संबंध में कोई फायदा या अनुतोष मांगने के लिए, या ऐसा फायदा या अनुतोष प्रदान करने में विफलता या विलम्ब के संबंध में, या किसी लोक प्राधिकार के कृत्यकरण में विफलता से, या उसके द्वारा राज्य में प्रवृत्त किसी विधि, नीति, सेवा, कार्यक्रम या योजना के उल्लंघन से उद्भूत किसी मामले के संबंध में, किसी नागरिक या नागरिकों के समूह द्वारा लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को किया गया कोई आवेदन, किन्तु इसमें किसी लोक सेवक, चाहे वह सेवारत हो या सेवानिवृत्त, के सेवा मामलों से संबंधित या किसी ऐसे मामले से संबंधित, जिसमें किसी न्यायालय या अधिकरण की अधिकारिता हो या सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं०-22) के अधीन किसी मामले या बिहार लोक सेवा के अधिकार अधिनियम, 2011 के अधीन अधिसूचित सेवाओं से संबंधित शिकायत सम्मिलित नहीं है;
- (ख) "लोक शिकायत निवारण का अधिकार" से अभिप्रेत है नियत समय-सीमा के भीतर किसी परिवाद पर नागरिकों को प्रदत्त सुनवाई एवं निवारण का कोई अवसर और परिवाद पर सुनवाई में किये गये विनिश्चय के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार ;
- (ग) "लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी" से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन अधिसूचित कोई लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ;
- (घ) "सूचना और सुकरण केन्द्र" से अभिप्रेत है, परिवाद दायर करने की सुविधा एवं मामले से संबंधित या जुड़ी हुई किसी प्रकार की सूचना के प्रसार के लिए राज्य पोर्टल, हेल्प डेस्क एवं सामान्य सहायता केन्द्र सहित धारा 5 के अधीन अधिसूचित या स्थापित केन्द्र या वेबसाइट ;
- (ङ.) "लोक प्राधिकार" से अभिप्रेत है राज्य सरकार और इसके विभाग और इसमें राज्य विधान-मण्डल द्वारा बनायी गयी किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित प्राधिकार या निकाय या संस्था सम्मिलित है ;
- (च) "प्रथम अपीलीय प्राधिकार" से अभिप्रेत है ऐसा अधिकारी या धारा 3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित प्राधिकार ;
- (छ) "द्वितीय अपीलीय प्राधिकार" से अभिप्रेत है ऐसा अधिकारी या धारा 3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित प्राधिकार ;
- (ज) "पुनरीक्षण प्राधिकार" से अभिप्रेत है ऐसा अधिकारी या धारा 3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित प्राधिकार ;
- (झ) "नियत समय-सीमा" से अभिप्रेत है किसी परिवाद पर सुनवाई का अवसर प्रदान करने वाले लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को, या किसी अपील का विनिश्चय करने के लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकार या द्वितीय अपीलीय प्राधिकार को, या यथास्थिति, परिवादी या अपीलार्थी को यथास्थिति, ऐसे परिवाद या अपील के विनिश्चय के बारे में सूचित करने के लिए पूर्वोक्त प्राधिकारियों को, अनुज्ञात अधिकतम समय-सीमा ;
- (ञ) "दिवस" से अभिप्रेत है समय-सीमा के रूप में निर्दिष्ट कार्य दिवस ;
- (ट) "विनिश्चय" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी या अपील प्राधिकार या पुनरीक्षण प्राधिकार द्वारा किसी परिवाद या अपील या पुनरीक्षण पर किया गया कोई विनिश्चय और इसमें यथास्थिति, परिवादी या अपीलार्थी को भेजी गई सूचना सम्मिलित है ;

(ठ) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित ; और

(ड) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार ।

3- **यह कानून राज्य सरकार, समय-समय पर, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकार, द्वितीय अपीलीय प्राधिकार, पुनरीक्षण प्राधिकार, राज्य प्राधिकार तथा नियत समय-सीमा को अधिसूचित कर सकेगी।**

4. **राज्य सरकार, समय-समय पर, विभागवार योजना, कार्यक्रम एवं सेवाओं को, जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा एवं लोक प्राधिकार एवं विभाग को जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा, अधिसूचित कर सकेगी।**

5- **लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी इस अधिनियम के अधीन दायर किये गये किसी परिवाद की सुनवाई का अवसर पक्षकारों को नियत समय-सीमा के भीतर देगा।**

(2) लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, ऐसे अन्य किसी अधिकारी, लोक पदाधिकारी या कर्मचारी की सहायता मांग सकेगा, जिसे वह उप धारा (1) के अधीन परिवाद की सुनवाई एवं निराकरण हेतु अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे।

(3) कोई भी अधिकारी, लोक प्राधिकार या कर्मचारी, जिसकी सहायता की मांग उप-धारा (2) के अधीन की गयी हो, वह सहायता मांगने वाले लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को समस्त सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के प्रयोजनार्थ, यथास्थिति, ऐसा अन्य अधिकारी या कर्मचारी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी माना जायेगा।

(4) नियत समय-सीमा उस तारीख से प्रारम्भ होगी, जिस तिथि को कोई परिवाद/अपील लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी या परिवाद प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को या प्रथम अपीलीय प्राधिकार या द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दायर किया गया हो। परिवाद की प्राप्ति की सम्यक् रूप से अभिस्वीकृति दी जायेगी।

(5) लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, उपधारा (1) के अधीन परिवाद प्राप्त होने पर, नियत समय-सीमा के भीतर परिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और परिवादी को सुनने के पश्चात् या तो उसे स्वीकार करते हुए या किसी अन्य विधि, नीति, सेवा, कार्यक्रम या योजना के अधीन उपलब्ध कोई वैकल्पिक फायदा या अनुतोष सुझाते हुए या उसे खारिज करते हुए, जिसके कारणों को लेखबद्ध किया जायेगा, परिवाद को विनिश्चित करेगा और नियत समय-सीमा के भीतर परिवाद पर अपने विनिश्चय से परिवादी को संसूचित करेगा।

6. **राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, सूचना और सुकरण केन्द्रों के संबंध में नियम बना सकेगी।**

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, सूचना और सुकरण केन्द्रों के संबंध में नियम बना सकेगी।

7- **कोई भी व्यक्ति, जिसे नियत समय-सीमा के भीतर सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो या जो लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के विनिश्चय से व्यथित हो, नियत समय-सीमा की समाप्ति से या लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के विनिश्चय की तारीख से तीस दिवस के भीतर, प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर कर सकेगा :**

परन्तु प्रथम अपीलीय प्राधिकार तीस दिवसों किंतु पैंतालीस दिवसों से अधिक नहीं की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारण से समय पर अपील दायर करने से वंचित रहा है।

(2) यदि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, धारा 5 के उपबंधों का पालन नहीं करे तो ऐसे अननुपालन से व्यथित कोई भी व्यक्ति सीधे प्रथम अपीलीय प्राधिकार को परिवाद प्रस्तुत कर सकेगा जिसे प्रथम अपील की रीति से निपटाया जायेगा।

(3) प्रथम अपीलीय प्राधिकार, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को उसके द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर परिवादी को सुनवाई एवं निराकरण का अवसर प्रदान करने का आदेश दे सकेगा या अपील खारिज कर सकेगा।

- (4) प्रथम अपीलीय प्राधिकार के विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील प्राधिकार, प्रथम अपीलीय प्राधिकार के विनिश्चय की तारीख से तीस दिवसों के भीतर द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दायर की जा सकेगी :
- परन्तु द्वितीय अपीलीय प्राधिकार, तीस दिवसों, किन्तु पैंतालीस दिवसों से अनधिक की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से वंचित रहा है ।
- (5) कोई व्यथित व्यक्ति सीधे द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर कर सकेगा, यदि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी उप-धारा (3) के अधीन पारित प्रथम अपीलीय प्राधिकार के आदेश का पालन नहीं करता है, या प्रथम अपीलीय प्राधिकार नियत समय सीमाओं के भीतर अपील का निपटारा नहीं करता है और उसे द्वितीय अपील की रीति से निपटाया जायेगा ।
- (6) द्वितीय अपीलीय प्राधिकार, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी या प्रथम अपीलीय प्राधिकार को, यथास्थिति परिवादी की सुनवाई एवं निवारण का अवसर प्रदान करने या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर जो किसी मामले में तीस दिवसों से अधिक नहीं होगा, अपील का निपटारा करने का आदेश दे सकेगा या अपील खारिज कर सकेगा ।
- (7) द्वितीय अपीलीय प्राधिकार, परिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के आदेश के साथ-साथ, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी या अन्य कोई लोक प्राधिकार या प्रथम अपीलीय प्राधिकार पर धारा-8 के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ।
- (8) लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी प्रथम अपीलीय प्राधिकार और द्वितीय अपीलीय प्राधिकार को इस धारा के अधीन किसी परिवाद या अपील का विनिश्चय करते समय वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं०-5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात्:-
- (क) किसी भी व्यक्ति का सम्मन करना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ।
- (ख) किसी दस्तावेज या साक्ष्य के रूप में पेश की जा सकने वाली तात्त्विक सामग्री को प्रकट करना और प्रस्तुत करना ।
- (ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना ।
- (घ) किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा करना ।
- (ङ.) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना ।
- (च) अपने विनिश्चयों, निदेशों और आदेशों का पुनर्विलोकन करना और/या
- (छ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाय ।

8- 'MLr A & (1) जहां द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के विचार में यह हो कि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी या अन्य कोई लोक प्राधिकार या प्रथम अपीलीय प्राधिकार, बिना किसी पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण के, नियत समय-सीमा के भीतर सुनवाई एवं निवारण का अवसर प्रदान करने में विफल रहा है, वहां वह उस पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो पांच सौ रुपये से कम किन्तु पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होगी ;

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व उस व्यक्ति को, जिस पर शास्ति अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित हो, सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा ।

- (2) उपधारा (1) के अधीन द्वितीय अपीलीय प्राधिकार द्वारा अधिरोपित शास्ति लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी या अन्य किसी लोक प्राधिकार या प्रथम अपीलीय प्राधिकार के वेतन से वसूलनीय होगी ।
- (3) द्वितीय अपीलीय प्राधिकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी या अन्य कोई लोक प्राधिकार या प्रथम अपीलीय प्राधिकार, पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण बतलाये बिना, इस अधिनियम के अधीन उसको समनुदेशित कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहा है, तो उस पर लागू सेवा नियमों के अधीन उसके विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगा ।

9. i qj h[k k A — इस अधिनियम के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के किसी आदेश द्वारा व्यथित लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी या अन्य लोक प्राधिकार या प्रथम अपीलीय प्राधिकार, उस आदेश की तारीख से साठ दिवसों की कालावधि के भीतर, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकार के समक्ष उस आदेश के पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकेगा । नामनिर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकार विहित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन का निपटारा करेगा :

परन्तु राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकार साठ दिवसों के पश्चात् किन्तु पचहत्तर दिवसों से अनधिक की कालावधि की समाप्ति के पूर्व किसी आवेदन को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक समय पर अपील दायर करने से, पर्याप्त कारण से, वंचित रहा है ।

10. **l nHkoi wZl dh xbZ dkjZkbZ dk l j{k.k A** – अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी कृत्य के लिए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ संस्थित नहीं होंगी ।

11. **U; k; ky; ka dh vf/kdkfjrk dk ot Zl A** – किसी सिविल न्यायालय को किसी भी प्रश्न पर सुनवाई, विनिश्चय या कार्रवाई करने या किसी भी मामले का अवधारण करने की अधिकारिता नहीं होगी, जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकार, द्वितीय अपीलीय प्राधिकार या राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा सुने जाने, विनिश्चित किये जाने या कार्रवाई किये जाने या अवधारित किये जाने के लिए अपेक्षित हो ।

12. **fo|eku fof/k; ka ds vfrfjDr mi ca ka**—इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे और उनका अल्पीकरण में नहीं होंगे ।

13. **fu; e cukus dh 'kfDrA**—(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(ii) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम, इनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधान मंडल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मंडल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपांतरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिए तो तत्पश्चात्, ऐसे नियम केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपांतरण या निरसन उनके अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

(14) **dfBukb; ka dk fujkdj.k**।—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती हो तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, कोई भी ऐसी कार्रवाई कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो उस कठिनाई के निराकरण के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके इस प्रकार किये जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, राज्य विधान मंडल के सदन के समक्ष रखा जायेगा ।

मिस्र, , oagrq

सुशासन के कार्यक्रम 2010-15 के अनुसार राज्य सरकार संकल्पित है कि राज्य की जनता द्वारा समर्पित लोक शिकायतों का विहित समय सीमा के भीतर निवारण कराये जाने के लिए लोक शिकायत निवारण का अधिकार राज्य की जनता को दिया जाय। इस हेतु बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार विधेयक-2015 तैयार किया गया है। लोक शिकायत निवारण अधिकार राज्य की जनता को प्रशासन एवं सरकार से संबंधित शिकायतों/ परिवादों के नियत समय-सीमा के भीतर निष्पादित किये जाने, शिकायतों पर विचार के दौरान उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने तथा इस क्रम में राज्य प्रशासन को जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी एवं संवेदनशील बनाया जाना ही इस विधेयक का उद्देश्य है तथा इसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

भार-साधक सदस्य।

भार-साधक सदस्य।

पटना
दिनांक 04 अगस्त, 2015

प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 935-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>